असबाबे हिन्दुस्तान

Website- www.asbabehindustan.com

R.N.I.NO.:UPHIN/2013/49660

वर्ष– 14 : अंक–203 | हिन्दी दैनिक नगर संस्करण, | प्रयागराज, शनिवार,11 जुलाई, 2026 | पृष्ठ– 04 | मूल्यः 1 रूपये

दो दिवसीय दौरे पर न्यूजीलैंड पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी

कई अहम समझौतों पर करी बात

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज ऑस्ट्रेलिया दौरे का तीसरा दिन है। आज पीएम मोदी ऐतिहासिक मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम पहुंचे। इसके बाद प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रेलिया में विपक्ष के नेता एंगस टेलर से भी मुलाकात की। इसके बाद वे दो दिन के दौरे के लिए न्यूजीलैंड पहुंचे है। के इस लाइव ब्लॉग में पढ़ें प्रधानमंत्री के विदेश दौरे से जुड़े तमाम अपडेट्स प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ऑकलैंड पहुंच गए हैं। चार दशकों से अधिक समय में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह न्यूजीलैंड यात्रा है। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य उच्च स्तरीय वार्ता के माध्यम से भारत-न्यूजीलैंड संबंधों के सभी पहलुओं को मजबूत करना है। शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी ऑकलैंड में मौजूद भारतीय समुदाय को संबोधित भी करेंगे।

भारतीय समुदाय के सदस्य ने क्या कहा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न्यूजीलैंड को लेकर भारतीय समुदाय के एक सदस्य ने कहा, 'यह बहुत खास है। ऐसा 40 साल बाद हुआ है, जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जा रहा है। यह भारतीय समुदाय के लिए एक शानदार मौका है। यह दोनों देशों के लिए फायदेमंद है। दोनों देशों के पास देने के लिए अलग-अलग चीजें हैं। इसलिए, व्यापार हमेशा से रहा है, लेकिन यह संबंधों को मजबूत करने के बारे में है। इससे भी जरूरी बात यह है कि यह पक्का करना है कि लोग उन सेवाओं और उत्पादों को खरीद सकें जो दोनों देशों में उपलब्ध होंगे, क्योंकि टैरिफ सबसे बड़ा फैक्टर है।' रेवेन्यू मंत्री साइमन वॉट्स ने क्या कहा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर रेवेन्यू मंत्री साइमन वॉट्स ने कहा, 'न्यूजीलैंड के लिए यह बहुत खास पल है कि वह यहां प्रधानमंत्री मोदी की मेजबानी कर पा रहा है। यह सच में न्यूजीलैंड और भारत के बीच संबंधों की गहराई को और मजबूत करता है। मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर होना आपसी संबंधों के लिए एक बड़ा कदम है और यह न्यूजीलैंड में रहने वाले भारतीय समुदाय के लिए भी एक बड़ा कदम है।' न्यूजीलैंड के सांसद ने क्या कहा? - फोटो : ग्राफिक्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न्यूजीलैंड दौरे से पहले वहां के सांसद फिल ट्वायफोर्ड ने भारत को दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण उभरती ताकतों में से एक बताया। ऑकलैंड में आईएएनएस से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता सही समय पर हुआ है।

हनुमानगढ़ी मंदिर की सीढ़ियों पर नमाज पढ़ाने का पाप सपा-कांग्रेस ने किया : सीएम योगी

अयोध्या। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या के दौरे पर हैं। जहां पर उन्होंने 432 करोड़ की 217 परियोजनाओं का शुभारंभ किया और पूर्व मंत्री मुन्ना सिंह की मूर्ति का अनावरण भी किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या दौरे में बीकापुर में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए अयोध्या को 432 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इस मौके पर उन्होंने पूर्व मंत्री मुन्ना सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि लंबे समय तक अयोध्या विकास से दूर रही। सपा और कांग्रेस की सरकारों ने हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़वाने का काम किया। क्या कभी दिल्ली की जामा मस्जिद में कोई हनुमान चालीसा पढ़ सकता है। सपा-कांग्रेस के लोगों ने ये पाप किया है। उन्होंने कहा कि अयोध्या आज विकास और समृद्धि के वैभव की ओर बढ़ रही है। अगर मंशा साफ हो तो विका अपने आप होता है। आज अयोध्या में दिख रहा है कि जब प्रभु श्रीराम की कृपा और हनुमान जी का आशीर्वाद हो तो अयोध्या के सारे काम अपने आप ही होते हैं। जो 500 साल में नहीं हुआ वो करके दिखाया सीएम योगी ने कहा कि आज अयोध्या हवाईअड्डे के माध्यम से पूरे देश और दुनिया से जुड़ चुकी है। अयोध्या की पहचान बदल गई है। पहले सरयू का जल दूषित रहता था पर कोई सफाई नहीं होती थी क्योंकि सपा-कांग्रेस के लोग अयोध्या को बदनाम करते थे अब डबल इंजन की सरकार में अयोध्या का विकास हो रहा है। डबल इंजन की सरकारों ने बिना थके बिना रुके काम किया जिससे नगर की पहचान बदली। डबल इंजन की सरकारों ने अयोध्या में वो करके दिखाया है जो कि 500 साल में नहीं हो सका। अब अयोध्या विकास और विरासत के पथ पर आगे बढ़ रही है। दो नगर पंचायतों का नाम बदलने की घोषणाएं की इस दौरान उन्होंने दो महत्वपूर्ण घोषणाएं करते हुए खिरौनी सोहावल नगर पंचायत का नाम मां ज्वाला देवी नगर पंचायत तथा भरतकुंड-भदरसा नगर पंचायत का नाम भरत नगर भरतकुंड किए जाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने विकासखंड परिसर में स्थापित स्व मुन्ना सिंह की प्रतिमा का अनावरण भी किया। कार्यक्रम में विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को आवास की चाभियां सौंपीं।

पेपर उछाले अभद्र भाषा....सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता का हाईवोल्टेज ड्रामा?

घसीटकर बाहर निकाला गया

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। जिसमें एक याचिकाकर्ता ने कोर्टरूम में जमकर हंगामा किया और इस दौरान उन्होंने जजों को ही आदेश दे दिया। हंगामे पर उसे जबरन कोर्ट से निकाला गया। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान एक अजीब घटनाक्रम देखने को मिला। दरअसल एक याचिकाकर्ता ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। शुक्रवार को याचिका पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने खुद पैरवी की। इस दौरान याची अपना आपा खो बैठा और उसने कथित तौर पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और इतना ही नहीं पीठ को आदेश दिया कि वे उसकी याचिका पर लखनऊ एसीपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दें। क्या है मामला? यह घटना जस्टिस के. वी.

विश्वनाथन और जस्टिस आलोक आराधे की पीठ के समक्ष हुई। सुनवाई शुरू होते ही याचिकाकर्ता ने असामान्य रूप से पीठ के सामने तल्ख लहजा अपनाया। काले कोट में, लेकिन वकीलों की बैंड के बिना पेश हुए याचिकाकर्ता ने पीठ से कहा, 'मिस्टर ज्यूडिशियल सर्वेंट, मैं आपको आदेश देता हूंकि लखनऊ के एसीपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दें।' इस पर हैरान जस्टिस विश्वनाथन ने पूछा, 'आप मुझे आदेश दे रहे हैं? आप हमें आदेश दे रहे हैं?' याचिकाकर्ता ने जवाब दिया, 'मुझे बस इतना ही कहना है। सब कुछ रिकॉर्ड पर है।' इसके बाद उसने कथित तौर पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और अपने केस से जुड़े दस्तावेज हवा में उछाल दिए। घटना के तुरंत बाद सुरक्षाकर्मियों ने हस्तक्षेप किया और याचिकाकर्ता को काबू में लेकर कोर्टरूम से बाहर ले गए। इसके बाद अदालत की कार्यवाही सामान्य रूप से जारी रही। फिलहाल, इस घटना को लेकर अदालत ने तत्काल कोई आदेश पारित नहीं किया है।

राहुल गांधी के सिखों पर दिए बयान पर दाखिल रिवीजन अर्जी खारिज

भगवान राम पर टिप्पणी मामले में 24 को सुनवाई

वाराणसी। राहुल गांधी के सिखों पर दिए बयान पर दाखिल रिवीजन अर्जी खारिज कर दी गई। यह मामला पिछले वर्ष सितंबर में राहुल गांधी के अमेरिका में दिए गए एक बयान से जुड़ा है। उधर, भगवान राम पर टिप्पणी मामले में 24 जुलाई को सुनवाई होगी। विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए) यजुवेंद्र विक्रम सिंह की अदालत ने बृहस्पतिवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा अमेरिका यात्रा के दौरान भारत में सिखों को लेकर दिए गए बयान के मामले में दाखिल रिवीजन अर्जी खारिज कर दी। अदालत ने पिछली सुनवाई में आदेश सुरक्षित रख लिया था। इस मामले में राहुल गांधी को पक्षकार बनाया गया था। यह मामला पिछले वर्ष सितंबर में राहुल गांधी के अमेरिका में दिए गए एक बयान से जुड़ा है। तिलमापुर, सारनाथ निवासी नागेश्वर मिश्र ने इस बयान को देश में गृहयुद्ध भड़काने की साजिश करार दिया था। राहुल गांधी के खिलाफ भगवान राम पर टिप्पणी

मामले में सुनवाई 24 जुलाई को अमेरिका के बोस्टन में भगवान श्रीराम पर कथित अमर्यादित टिप्पणी के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दाखिल परिवाद पर बृहस्पतिवार को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एमपी-एमएलए) नीरज त्रिपाठी की अदालत में सुनवाई हुई। राहुल गांधी के अधिवक्ताओं ने वकालतनामा दाखिल कर अपना पक्ष रखने के लिए समय मांगा। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 24 जुलाई की तारीख तय की है। पिछले दिनों सत्र न्यायालय ने निगरानीकर्ता की निगरानी अर्जी स्वीकार करते हुए अवर न्यायालय को पुनः सुनवाई करने का आदेश दिया था। इसी आदेश के अनुपालन में बृहस्पतिवार को सुनवाई हुई। एडवोकेट हरिशंकर पांडेय ने अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (चतुर्थ) एमपी-एमएलए कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। अर्जी में कहा गया है कि राहुल गांधी 21 अप्रैल 2025 को अमेरिका के बोस्टन में ब्राउन यूनिवर्सिटी में छात्रों के साथ एक सत्र में शामिल हुए थे। आरोप है कि वहां उन्होंने भगवान श्रीराम को "पौराणिक" बताया था। उन्होंने उस युग की कहानियों को काल्पनिक भी कहा था। अर्जी में यह भी आरोप है कि राहुल गांधी ने भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाकर करोड़ों हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। उन पर राम मंदिर का विरोध करने और विदेश में भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाने का भी आरोप है। इस मामले में दाखिल अर्जी को 27 मई 2025 को अवर न्यायालय ने खारिज कर दिया था। इसके बाद परिवादी अधिवक्ता हरिशंकर पांडेय ने सत्र न्यायालय में निगरानी अर्जी दाखिल की थी। सत्र न्यायालय ने सुनवाई के बाद अवर न्यायालय को इस अर्जी पर पुनः सुनवाई करने का आदेश दिया था।

सार संक्षेप

अधिक अल्कोहलयुक्त दवाओं की बिक्री के लिए लाइसेंस और डॉक्टर के पर्चे की होगी अनिवार्यता: सरकार

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को अधिक मात्रा में एथिल अल्कोहल (इथेनॉल) युक्त औषधीय फॉर्मूलेशनों (दवाओं) के नियमन को सख्त कर दिया। सरकार ने ऐसे उत्पादों की बिक्री के लिए लाइसेंस और डॉक्टर के पर्चे को अनिवार्य कर दिया है। इस कदम का उद्देश्य इन दवाओं के दुरुपयोग पर रोक लगाना और साथ ही वास्तविक चिकित्सीय जरूरतों के लिए उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करना है। मंत्रालय ने बताया कि इलायची, अदरक और अन्य सुगंधित औषधीय फॉर्मूलेशन की टिंचर (अर्क) जैसी कई औषधीय तैयारियों को पहले अनुसूची-के के तहत लाइसेंस संबंधी आवश्यकताओं से छूट प्राप्त थी। हालांकि, इनमें से कुछ उत्पादों में 80 से 90 प्रतिशत तक एथाइल अल्कोहल होता है, जिससे इनके नशे के उद्देश्य से दुरुपयोग की आशंका रहती है। केंद्र सरकार ने यह भी बताया कि कुछ राज्य सरकारों ने ऐसे उत्पादों के दुरुपयोग को लेकर चिंता जताते हुए इस संबंध में सुझाव और संदर्भ भेजे थे। इस समस्या के समाधान के लिए सरकार ने तय किया है।

158 वर्ष बाद अरुणाचल प्रदेश में फिर दिखा दुर्लभ हिमालयी पुष्प सियानैंथस हूकेरी

ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में वैज्ञानिकों ने एक महत्वपूर्ण वनस्पति खोज करते हुए दुर्लभ हिमालयी पुष्प सियानैंथस हूकेरी को 158 वर्ष बाद भारत में पुनः दर्ज किया है। यह प्रजाति भारत में अंतिम बार वर्ष 1867 में सिक्किम में दर्ज की गई थी। इस खोज ने पूर्वी हिमालय की समृद्ध जैव विविधता को एक बार फिर वैश्विक स्तर पर रेखांकित किया है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण (बीएसआई) के वैज्ञानिकों ने सितंबर 2025 में तवांग जिले के मागो गांव के निकट चुना घाटी में लगभग 3600 मीटर की ऊंचाई पर इस पौधे को खोजा। अल्पाइन घास के मैदानों और पथरीली ढलानों पर इसके कुछ ही पौधे पाए गए। शोधकताओं ने नमूनों को सुरक्षित कर केंद्रीय राष्ट्रीय हर्बेरियम, हावड़ा में जमा कराया है। घंटी के आकार के बैंगनी-नीले फूलों वाला यह छोटा शाकीय पौधा कठोर पर्वतीय परिस्थितियों के अनुकूल है। यह प्रायः अगस्त और सितंबर के बीच खिलता है तथा पूर्वी हिमालय के सीमित क्षेत्रों में ही पाया जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार, भारत में इस प्रजाति के 50 से भी कम परिपक्व पौधे शेष हैं। इसी कारण शोधकताओं ने इसे देश में आईयूसीएन मानकों के अनुसार संकटग्रस्त श्रेणी में रखने की सिफारिश की है।

मुझे चुप कराने के लिए आपको मुझे मारना पड़ेगा

ममता की खुली चुनौती से बढ़ेगा सियासी पारा?

ममता बनर्जी के हाथ से सत्ता जा चुकी है और पार्टी बगावत से जूझ रही है, लेकिन टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी के तेवरों में कोई कमी नहीं आई है। उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी कर सत्ताधारी भाजपा को चुनौती दी है और कहा है कि अगर उन्हें चुप कराना है तो उन्हें मारकर ही ऐसा किया जा सकता है। आइए जानते हैं कि ममता बनर्जी ने वीडियो संदेश में और क्या-क्या बातें कही हैं। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को एक वीडियो संदेश जारी किया। इस वीडियो संदेश में ममता बनर्जी ने भाजपा पर तीखा हमला बोला और सत्ताधारी दल पर टीएमसी के नेताओं और कार्यकताओं को निशाना बनाने का आरोप लगाया। ममता बनर्जी ने कहा कि 'अगर सत्तारूढ़ पार्टी उन्हें चुप कराना चाहती है या टीएमसी को खत्म करना

चाहती है तो उसके लिए पहले उन्हें मुझे मारना होगा।' ममता बनर्जी ने वीडियो संदेश में क्या-क्या आरोप लगाए? वीडियो संदेश में ममता बनर्जी ने टीएमसी पार्टी में हो रही बगावत और टीएमसी नेताओं के कथित शोषण पर अपनी बात रखी। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा उनकी पार्टी के नेताओं और कार्यकताओं को डराने-धमकाने में लगी है। ममता बनर्जी ने कहा कि टीएमसी के कई नेताओं पर हमले हुए हैं और उनका अपमान किया गया है। इनमें महुआ मोइत्रा, अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी जैसे वरिष्ठ नेता शामिल हैं। ममता बनर्जी ने कहा, 'आप ने किस पर हमला नहीं किया है? आपने महुआ, अभिषेक बनर्जी, कल्याण बनर्जी पर हमला किया। आपने मेरे घर पर हमला किया।' ममता बनर्जी का यह वीडियो संदेश ऐसे समय आया है, जब टीएमसी पार्टी बड़ी चुनौतियों से निपट रही है। पार्टी में अंदरुनी मतभेद और बगावत उभरी है और पार्टी में टूट का खतरा है। बागी विधायक ऋतब्रत बनर्जी को करीब 60 विधायकों का समर्थन मिला हुआ है। ममता बनर्जी ने वीडियो संदेश में दावा किया कि उनके कई सहयोगियों से पुलिस हिरासत में अमानवीय व्यवहार किया गया। टीएमसी प्रमुख ने कहा, 'मेरे कई सहयोगी जेल में बंद हैं, उन्हें फर्श पर सोने को मजबूर किया जा रहा है। कुछ को कमर में रस्सियां और पैरों में हथकड़ियां डालकर घुमाया जा रहा है। कुछ के सिर मुंडवा दिए गए हैं। कईयों पर घिनौनी चीजें फेंकी गई हैं, जिनका जिक्र करना भी शर्मनाक है।' तृणमूल कांग्रेस में टूट जारी ममता बनर्जी का यह वीडियो संदेश ऐसे समय सामने आया है, जब उनकी पार्टी में लगातार टूट जारी है। गुरुवार को टीएमसी के तीन पूर्व सांसद भाजपा में शामिल हो गए। इनमें सुष्मिता देव, सुखेंदु शेखर राय और प्रकाश चिक बराइक का नाम शामिल है। कोलकाता के साल्ट लेक स्थित भाजपा कार्यालय में तीनों नेताओं ने भाजपा की सदस्यता ली। गुरुवार को ममता बनर्जी ने एक बयान में बागी नेताओं को निशाने पर लिया था और उन पर पार्टी के साथ गद्दारी करने का आरोप लगाया। ममता बनर्जी ने कहा कि 'लोगों को उन टीएमसी नेताओं को माफ नहीं करना चाहिए, जो गद्दार हैं और भाजपा के साथ मिल गए हैं। दो नावों पर सवार होने की कोशिश न करें, अभी भी पीछे मुड़कर देखने और बर्बरता पर ध्यान देने की जरूरत है।

महादेव ऑनलाइन बेटिंग केस में ईडी की बड़ी कार्रवाई

940.77 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच

नईदिल्ली। महादेव ऑनलाइन बुक और स्काईएक्सचेंज से जुड़े कथित अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 940.77 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियां अस्थायी रूप से अटैच की हैं। यह कार्रवाई ईडी के रायपुर जोनल कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत की है। ईडी के अनुसार, अटैच की गई संपत्तियां विकास गर्ग, उनके परिवार के सदस्यों तथा उनके स्वामित्व एवं नियंत्रण वाली कंपनियों से संबंधित हैं। इनमें रिहायशी मकान, भूमि के भूखंड, इक्विटी शेयर और अन्य प्रतिभूतियां शामिल हैं। यह कार्रवाई महादेव ऑनलाइन बुक और स्काईएक्सचेंज से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच का हिस्सा है। ईडी ने इस मामले की जांच छत्तीसगढ़ के दुर्ग पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर और छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल समेत विभिन्न राज्यों में दर्ज अन्य एफआईआर के आधार पर शुरू की थी। इन मामलों में अवैध ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म के संचालकों, प्रमोटरों और उनके सहयोगियों पर आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप लगाए गए हैं। जांच में ईडी को पता चला कि यह बेटिंग सिंडिकेट विदेश से संचालित फ्रेंचाइजी आधारित पैनल नेटवर्क के माध्यम से काम करता था।

संपादकीय

जिम्मेदारी न लेने का घातक रोग

नोटबंदी, लॉकडाउन, चीन की घुसपैठ, पुलवामा और पहलगाम जैसे आतंकी हमले, मणिपुर में जनजातीय संघर्ष, बारिश, सूखा आदि की आपदाएं, पेपर लीक न जाने कितने मामलों में जनता को जान-माल हर तरह का नुकसान हुआ। अभी राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के कारण भावनात्मक तौर पर भी जनता बुरी तरह आहत है। लेकिन प्रधानमंत्री ने कभी इन मामलों में आगे बढ़कर जिम्मेदारी नहीं ली या किसी गलत फैसले के लिए माफी नहीं मांगी, इस्तीफा देना तो दूर की बात है। वहीं आम जनता में से कोई जब किसी मामले पर सरकार की आलोचना करने तो उसे कैसे कानूनी शिकंजे में जकड़ा जाता है, इसकी बड़ी मिसाल उमर खालिद की गिरफ्तारी है। विपक्ष सरकार की आलोचना करे, तो नरेन्द्र मोदी उसे व्यक्तिगत निंदा मानकर कहते हैं कि गालियां उनके लिए टॉनिक का काम करती हैं। अब नरेन्द्र मोदी की राह पर ही देवेन्द्र फड़नवीस चल पड़े हैं। महाराष्ट्र में थोड़े दिनों की बारिश से हाहाकार मच चुका है। कई लोगों की जान चली गई है। 7,000 करोड़ रुपए की लागत वाले और हाल ही में शुरू किए मुंबई-पुणे मिसिंग लिंक्ड एक्सप्रेसवे पर जो भूस्खलन हुआ और करीब 18 घंटे यातायात बंद रहा, तो विपक्ष ने सरकार पर सवाल उठाए। साथ ही सोशल मीडिया पर भी सरकार की खिंचाई हुई। यह मुद्दा विधानसभा में भी उठा। विधानसभा में शहरों के विकास पर नियम 293 के तहत जब बहस हो रही थी तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विपक्ष पर कड़ा हमला करते हुए इस परियोजना को इंजीनियरिंग का एक शानदार वैश्विक नमूना करार दिया। उन्होंने कहा कि देवेंद्र फडणवीस को बुरा-भला कहना ठीक है। मुझे इसकी आदत है। मुझ पर इन बातों का कोई असर नहीं होता। मैंने जिंदगी में एक बात सीखी है, आज से 10 साल बाद, जो लोग आज बुरा-भला कह रहे हैं, वे शायद दिखाई न दें, लेकिन प्रकनेक्टिंग लिंक्ड कायम रहेगा, और उस पर देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के नाम होंगे। आप मुझे जितना चाहें बदनाम करें, लेकिन अगर आप महाराष्ट्र को बदनाम करेंगे, तो मैं किसी को भी नहीं बख्शूंगा। इसके बाद अपनी भाषा का स्तर प्रचलित भाजपाई राजनीति के अनुरूप गिराते हुए फडणवीस ने कहा कि जिनको कुत्ता भी नहीं पूछा, वो आजकल सोशल मीडिया पर आकर सबको गाली देते हैं, मुख्यमंत्री को भी गाली देते हैं। ऐसे भाड़े के टट्टू इस मिसिंग लिंक के बारे में भी पैसा ले-लेकर सोशल मीडिया पर लिख रहे थे, ऐसे लोगों का कह देना चाहता हूं कि अगर महाराष्ट्र का अपमान करोगे तो छोड़ूंगा नहीं। देवेन्द्र फड़नवीस ने सदन की गरिमा को हाशिए पर धकेलते हुए कुत्ते जैसे असंसदीय शब्द का इस्तेमाल किया और पर जिस तरह सदन में सत्ता पक्ष के लोगों ने उनका समर्थन किया, उससे जाहिर होता है कि सरकार को लोकतांत्रिक शालीनता और मर्यादा की कोई परवाह नहीं है। सोशल मीडिया पर पैसे लेकर ट्रोलिंग का काम भाजपा के शासन में ही खूब बढ़ा है और इसके पीछे किन लोगों का समर्थन रहा है, यह जनता जानती है। वैसे अगर संरचनात्मक गड़बड़ियों पर सरकार से ही जवाब मांगा जाएगा, इस पर भाजपा सरकार के लोग चिढ़ते क्यों हैं, यह समझ से परे है। हाल ही में एक वाकया उत्तरप्रदेश से सामने आया है, जब पत्रकार ने मंत्री दिनेश प्रताप सिंह से सवाल किया कि मुख्यमंत्री के उद्घाटन से पहले ही लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे कई जगह से धंस गया है। तो दिनेश प्रताप सिंह ने जवाब दिया कि इसमें कौन सी नयी बात है, आप सड़क खुद बनवा लो। उन्होंने सड़कों की टूट-फूट और मरम्मत को एक प्रक्रिया का हिस्सा बताया। बेशक सड़कें टूटती हैं, उनमें गड्ढे बनते हैं, लेकिन जब वे कई बरसों तक इस्तेमाल हो जाएं तब उनकी मरम्मत की नौबत आनी चाहिए। अगर उद्घाटन से पहले या शुरू होने के चंद दिनों में सड़कें, पुल या कोई भी इमारत टूटे तो जाहिर है कि इसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। इस समय अकेले महाराष्ट्र या उत्तरप्रदेश से नहीं, बल्कि गुजरात, राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली कई राज्यों में कहीं सड़कें टूटीं, कहीं एयरपोर्ट पानी-पानी हुआ, कहीं स्टेशन पर पंखे से पानी गिरने लगा। ऐसी तस्वीरें देखकर समझा जा सकता है कि विकास के नाम पर जनता के दिए टैक्स से जो भारी-भरकम परियोजनाएं बन रही हैं, उनकी लागत का बड़ा हिस्सा भाजपा नेताओं, अधिकारियों या ठेकेदारों की जेब में जा रहा है। दिक्कत यह है कि भारतीय जनता ने इस भ्रष्टाचार को अब सामान्य आचरण मानकर स्वीकार कर लिया है। फिर भी कभी सवाल उठाए जाते हैं तो ऐसे ही जवाब मिलते हैं कि खुद बनवा लो या जिनको कुत्ता नहीं पूछता वो सवाल पूछ रहे हैं। सरकार की आलोचना को राष्ट्रहित आलोचना माना जाने लगा है या फिर देश विरोधी काम। जबकि हाल ही में महाराष्ट्र में ही जस्टिस माधव जामदार ने सरकार विरोधी नारे लगाने पर एक व्यक्ति को तड़ीपार करने के आदेश पर पुलिस को फटकार लगाई और साफ कहा कि किसी नेता के खिलाफ नारे लगाना देशविरोधी काम नहीं है। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐसा ही फैसला सुनाया था कि सरकार की आलोचना देश की आलोचना नहीं है। हम नहीं जानते कि देवेंद्र फड़नवीस ने इस फैसले को सुना या नहीं, मगर यह तय है कि वे पूरी तरह नरेन्द्र मोदी के नक्शेकदमों पर चल रहे हैं। देवेन्द्र फड़नवीस का मानना है कि आज से दस साल बाद भी परियोजनाओं पर उनका नाम रहेगा, यह बिल्कुल सही बात है क्योंकि आज से 60-70 साल पहले जो काम कांग्रेस की सरकारों में हुआ है, उनका नाम अब भी बना ही हुआ है। भले आज भाजपा कांग्रेस सरकारों के काम को नकारे। असल बात तो यह है कि सरकार किसी भी दल की हो, जनता उसे काम करने के लिए सत्ता सौंपती है इसलिए काम किया जाए, तो उसका एहसान नहीं जताया जा सकता।

असहमति और विरोध का सिमटता दायरा और उम्मीद के स्वर

सरकार के सामने अपनी अपेक्षाएं रखते हैं। सरकार या अन्य प्रभावशाली तबकों की मनमानी के खिलाफ भावनाओं का इजहार करते हैं। यह प्रजातांत्रिक व्यवस्था की जरूरी शर्त है। इसलिए किसी को नुकसान पहुंचाए बिना विरोध व्यक्त करने के तरीकों को सभी वास्तविक लोकतांत्रिक देशों में संवैधानिक और सामाजिक मान्यता मिली है। लिहाजा, सवाल उठता है कि क्या संसद से लेकर गांवों तक अपने प्रतिनिधि चुनने वाले भारत में लोगों को सही अर्थों में अभिव्यक्ति की आजादी हासिल है या नहीं? क्या मीडिया और अन्य नागरिक संगठन अपनी मर्जी से काम करने के लिए स्वतंत्र है?
बहरहाल,पूर्ण स्वतंत्रता जैसी आदर्श स्थिति तो कल्पना से परे है। अगर धरती पर कोई स्वर्ग होता तो शायद वहां भी पूरी आजादी नहीं मिल सकती थी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में बोलने और लिखने की आजादी का प्रावधान है।

राजेश पांडेय

कानून और मयार्दा के दायरे में असहमति और विरोध जताने की आजादी स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है। इसके माध्यम से लोग अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं। सरकार के सामने अपनी अपेक्षाएं रखते हैं। सरकार या अन्य प्रभावशाली तबकों की मनमानी के खिलाफ भावनाओं का इजहार करते हैं। यह प्रजातांत्रिक व्यवस्था की जरूरी शर्त है। इसलिए किसी को नुकसान पहुंचाए बिना विरोध व्यक्त करने के तरीकों को सभी वास्तविक लोकतांत्रिक देशों में संवैधानिक और सामाजिक मान्यता मिली है। लिहाजा, सवाल उठता है कि क्या संसद से लेकर गांवों तक अपने प्रतिनिधि चुनने वाले भारत में लोगों को सही अर्थों में अभिव्यक्ति की आजादी हासिल है या नहीं? क्या मीडिया और अन्य नागरिक संगठन अपनी मर्जी से काम करने के लिए स्वतंत्र है? बहरहाल,पूर्ण स्वतंत्रता जैसी आदर्श स्थिति तो कल्पना से परे है। अगर धरती पर कोई स्वर्ग होता तो शायद वहां भी पूरी आजादी नहीं मिल सकती थी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में बोलने और लिखने की आजादी का प्रावधान है। असहमति और असंतोष समाज को दबावों से मुक्त करने के कारगर औजार हैं। लेकिन देश के कई राज्यों में बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी को कुचलने की प्रवृत्ति बढ़ी है। धरना, रैली के माध्यम से सरकार के फैसलों का विरोध करने वालों के खिलाफ पुलिस कई बार सख्त कार्रवाई करती है। इसलिए बम्बई हाईकोर्ट के जस्टिस माधव जयाजीराव जामदार का यह कथन उम्मीद जगाता है कि क्या सभी नागरिक भारत सरकार के गुलाम हैं? जस्टिस जामदार ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा एक राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता को नागरिकता कानून में संशोधन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और नारे लगाने पर एक साल के लिए जिलाबदर करने के आदेश को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की है। अदालत ने

अपने आदेश में कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 में नागरिकों को अपनी राय व्यक्त करने और शान के साथ रहने का अधिकार है। लोगों को जनहित के मुद्दों पर अपनी आवाज उठाने का हक है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि पुलिस अधिकारी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के सेवक नहीं बल्कि जनता के सेवक हैं। जस्टिस जामदार की टिप्पणी ध्रुवीकरण और संवैधानिक संस्थाओं को महत्वहीन बनाने की कोशिश के दौर में बेहद अहम है। आम नागरिक की स्वतंत्रता का दायरा सिमट रहा है। उस पर लगातार संदेह और दबाव बढ़ा है। अभी हाल के कुछ फैसलों और मामलों पर नजर डालें तो लोगों को कदम-कदम पर परीक्षा देना पड़ रहा है। मतदाता सूचियों के विशेष पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया में वोटर पर अपनी पहचान साबित करने की पूरी जिम्मेदारी डाल दी गई है। तार्किक विसंगति जैसा अटपटा और अनोखा प्रावधान वोटर को मतदाता सूची में शामिल करने की बजाय बाहर करने से ज्यादा प्रेरित नजर आता है। पश्चिम बंगाल की एसआईआर का एक करिश्मा अभी हाल ही प्रकाश में आया है। कोलकाता के अंग्रेजी अखबार टेलीग्राफ के पूर्व संपादक आर राजगोपाल के पासपोर्ट का नवीनीकरण खटाई में पड़ गया। दरअसल, एसआईआर के दौरान उनका नाम मतदाता सूची से बाहर हो गया है। पासपोर्ट में देर के कारण वे अपनी बेटी की शादी में शामिल होने के लिए अमेरिका नहीं जा पाए। अभी हाल में विदेश मंत्रालय ने यह कहकर लोगों की चिंता बढ़ा दी है कि पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं है। इससे नया विवाद खड़ा हो गया है। लोगों की पहचान से जुड़े कई दस्तावेज सरकार जारी करती है। फिर उन पर खुद सवाल उठाती है। एक अन्य फैसला नागरिक समाज पर सरकार की गहराती छाया की तस्वीर दिखाता है। विदेशी अंशदान विनियमन नियम (एफसीआरए) 2026 में संशोधन के जरिये विदेशी धन लेने वाले अशासकीय संगठनों (एनजीओ) को अपनी गतिविधियों को परिभाषित करना पड़ेगा, कामकाज का क्षेत्र बताना होगा और कई सूक्ष्म जानकारियां सरकार को देना होंगी। जाहिर है, ऐसे नियमों से अशासकीय संगठनों पर सरकार का शिकंजा मजबूत होगा। कुछ एनजीओ शिक्षा, स्वास्थ्य और कई अन्य क्षेत्रों में अच्छा मैदानी काम करते हैं। वे जरूरी मुद्दों पर जनमत जगाते हैं। नए नियम उनकी गतिविधियों पर असर डालेंगे। सरकार ने विदेशी धन के दुरुपयोग और गैरकानूनी धर्मपरिवर्तनों पर चिंता जताते हुए विदेशी सहायता लेने वाले एनजीओ पर नजर रखने के लिए कड़े नियम बनाए हैं। यहां अतीत की स्थिति पर नजर डालना भी उचित होगा। आम नागरिकों, मीडिया, गैर सरकारी संगठनों पर सरकार की पैनी नजर रखने के प्रावधान सिर्फ बीते दस-बारह सालों में नहीं किए गए हैं। पहले भी सरकारें मीडिया और सिविल सोसायटी पर अंकुश लगाने के उपाय करती रही हैं। मिसाल के तौर पर देश में सबसे पहले सेंसरशिप इमरजेंसी के दौरान (1975-1977) लागू हुई थी। उस वक्त जानकारी के मुख्य स्त्रोत अखबार और सरकारी रेडियो, टेलीविजन (बहुत सीमित क्षेत्र में) थे। अखबारों के दफ्तरों में केंद्र सरकार के प्रेस सूचना ब्यूरो के अफसरों का आना-जाना रहता था। पीटीआई, यूएनआई, समाचार भारती और हिंदुस्तान समाचार को मिलाकर बनी सिर्फ एक न्यूज एजेंसी श्समाचारश काम करती थी। सभी अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय और प्रादेशिक समाचार एक स्त्रोत से आते थे। आपातकाल के दौरान सरकार की सख्ती के कारण अधिकतर अखबार सरकार की लाइन पर चलते थे। इस संबंध में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी की टिप्पणी गौरतलब है। इमरजेंसी के बाद उन्होंने कहा था, सरकार ने तो अखबारों से बैठने के लिए कहा था लेकिन वे तो उसके सामने जमीन पर लेट गए थे। 1976 में एफसीआरए कानून लागू किया गया था। उसमें 2010 में कुछ और सख्त प्रावधान किए गए। 2020 में सहयोगी संगठनों को विदेशी अंशदान ट्रांसफर करने पर रोक लगाई गई। इसका असर संगठनों के कामकाज पर पड़ा है। पिछले 12 वर्षों में मार्च 2026 तक लगभग बीस हजार संगठनों के एफसीआरए लायसेंस खत्म हो गए हैं। असहमति और विरोध को कुचलने का सुनियोजित दौर 2014 से ज्यादा तेज हुआ है। अलबत्ता 2024 के बाद उसमें थोड़ी गिरावट आई है। लोकसभा में 240 सीटों के साथ स्पष्ट बहुमत न मिलने के कारण सरकार के तीखे तेवर ढीले पड़े हैं। फिर भी, सरकार एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ईडी) की घनघोर सक्रियता से विरोध को दबाने की कोशिश कर रही है। ईडी ने विपक्षी दलों के नेताओं की नाक में दम कर रखा है। लोकसभा और विधानसभा चुनावों से पहले ईडी की हलचल कुछ ज्यादा ही तेज रहती है। ऐसी खबरें कई बार आई हैं कि 2014 से 2024 के बीच ईडी की 90 प्रतिशत से अधिक कार्रवाई विपक्षी नेताओं के खिलाफ हुई है। मीडिया भी ईडी की चपेट में आया है।

दिल्ली की ईवी नीति: क्या स्वच्छ हवा की राह इलेक्ट्रिक होगी?

किसी ने सोचा होगा कि वही शहर आज इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का वैश्विक उदाहरण बन जाएगा। चीन सरकार ने शहरी परिवहन में इलेक्ट्रिक बसों व टैक्सियों का बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया। इससे वायु गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार हुआ, हालांकि प्रदूषण पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। दिल्ली आज बहुस्तरीय प्रदूषण संकट से जूझ रही है। सर्दियों में धीमी हवाओं और तापमान उलटाव से जहरीली हवा फंस जाती है। वाहनों का दबाव, निर्माण व औद्योगिक धूल, पराली जलाने का धुआं और कचराध्बायोमास दहन प्रदूषण को और गहरा करते हैं। आसपास के कोयला आधारित बिजलीघर और मथुरा रिफायनरी से निकलने वाले सल्फर डाइऑक्साइड व नाइट्रोजन ऑक्साइड भी वायु गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। इन सबके संयुक्त प्रभाव से सार्वजनिक स्वास्थ्य पर गंभीर संकट खड़ा होता है और सरकारों के सामने ऊर्जा संक्रमण, क्षेत्रीय सहयोग तथा शहरी परिवहन सुधार जैसी चुनौतियां उपस्थित होती हैं। इन परिस्थितियों के बीच दिल्ली सरकार द्वारा अधिसूचित नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2026 केवल परिवहन नीति नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा संक्रमण की दिशा में एक महत्वाकांक्षी पहल के रूप में सामने आई है। भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की यात्रा केवल राज्यों की पहल तक सीमित नहीं रही। केंद्र सरकार ने 2015 में फेम इंडिया योजना शुरू की, जिसे बाद में फेम-11 के रूप में विस्तारित किया गया। अनुदान, बैटरी निर्माण, चार्जिंग अवसंरचना तथा पीएम ई-ड्राइव जैसी पहलों के माध्यम से केंद्र सरकार ने केवल वाहन खरीद ही नहीं बल्कि पूरे ईवी पारितंत्र को विकसित करने का प्रयास किया है। राष्ट्रीय प्रयासों के समानांतर अनेक राज्यों ने अपनी-अपनी इलेक्ट्रिक वाहन नीतियां बनाई हैं।

अरुण कुमार डनायक

लगभग डेढ़ दशक पहले बीजिंग दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में था। तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि वही शहर आज इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का वैश्विक उदाहरण बन जाएगा। चीन सरकार ने शहरी परिवहन में इलेक्ट्रिक बसों व टैक्सियों का बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया। इससे वायु गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार हुआ, हालांकि प्रदूषण पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। दिल्ली आज बहुस्तरीय प्रदूषण संकट से जूझ रही है। सर्दियों में धीमी हवाओं और तापमान उलटाव से जहरीली हवा फंस जाती है। वाहनों का दबाव, निर्माण व औद्योगिक धूल, पराली जलाने का धुआं और कचराध्बायोमास दहन प्रदूषण को और गहरा करते हैं। आसपास के कोयला आधारित बिजलीघर और मथुरा रिफायनरी से निकलने वाले सल्फर डाइऑक्साइड व नाइट्रोजन ऑक्साइड भी वायु गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। इन सबके संयुक्त प्रभाव से सार्वजनिक स्वास्थ्य पर गंभीर संकट खड़ा होता है और सरकारों के सामने ऊर्जा संक्रमण, क्षेत्रीय सहयोग तथा शहरी परिवहन सुधार जैसी चुनौतियां उपस्थित होती हैं। इन परिस्थितियों के बीच दिल्ली सरकार द्वारा अधिसूचित नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2026 केवल परिवहन नीति नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा संक्रमण की दिशा में एक महत्वाकांक्षी पहल के रूप में सामने आई है। भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की यात्रा केवल राज्यों की पहल तक सीमित नहीं रही। केंद्र सरकार ने 2015 में फेम इंडिया योजना शुरू की, जिसे बाद में फेम-11 के रूप में विस्तारित किया गया। अनुदान, बैटरी निर्माण, चार्जिंग अवसंरचना तथा पीएम ई-ड्राइव जैसी पहलों के माध्यम से केंद्र सरकार ने केवल वाहन खरीद ही नहीं बल्कि पूरे ईवी पारितंत्र को विकसित करने का प्रयास किया है। राष्ट्रीय प्रयासों के समानांतर अनेक राज्यों ने अपनी-अपनी इलेक्ट्रिक वाहन नीतियां बनाई हैं। दिल्ली के साथ-साथ, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल, हरियाणा और मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों ने ऐसी नीतियां लागू कीं, जिससे जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता घटे, प्रदूषण कम हो और हरित अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिले। दिल्ली ने वर्ष 2020 में देश की सबसे प्रगतिशील इलेक्ट्रिक वाहन नीतियों में से एक लागू की थी, जिसका आधार प्रोत्साहन था। खरीद पर सब्सिडी, सड़क कर एवं पंजीकरण शुल्क में छूट, चार्जिंग स्टेशनों का विस्तार और जन-जागरूकता अभियानों के माध्यम से लोगों को स्वेच्छा से इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। इसका सकारात्मक परिणाम यह हुआ कि दिल्ली देश के सबसे तेजी से बढ़ते इलेक्ट्रिक वाहन बाजारों में शामिल हो गई, विशेषकर दोपहिया वाहनों और ई-रिक्शा के क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष 2026 की नई नीति इसी यात्रा का अगला चरण है। यदि 2020 की नीति को प्रोत्साहन आधारित नीति कहा जाए, तो 2026 की नीति समयबद्ध परिवर्तन आधारित नीति है। अब सरकार केवल रियायतें देकर लोगों की स्वैच्छिक भागीदारी पर निर्भर नहीं रहना चाहती, बल्कि स्पष्ट समय-सीमा निर्धारित कर चरणबद्ध रूप से पेट्रोल और सीएनजी वाहनों से इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर संक्रमण सुनिश्चित करना चाहती है। इसी उद्देश्य से 1 जनवरी 2027 से केवल इलेक्ट्रिक ऑटो-रिक्शा तथा 1 अप्रैल 2028 से केवल इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के नए पंजीकरण का प्रावधान किया गया है। यही गुणात्मक परिवर्तन नई नीति को 2020 की नीति से अधिक साहसिक, स्पष्ट और दूरगामी बनाता है। यद्यपि नई नीति में इलेक्ट्रिक कारों की खरीद पर भी कर एवं पंजीकरण शुल्क में छूट सहित विभिन्न प्रोत्साहनों का प्रावधान है, फिर भी सरकार का मुख्य जोर दोपहिया वाहनों के विद्युतीकरण पर है, क्योंकि दिल्ली के लगभग दो-तिहाई पंजीकृत वाहन इसी श्रेणी के हैं। इनके विद्युतीकरण से वायु प्रदूषण, ईंधन खपत और कार्बन उत्सर्जन में सबसे अधिक कमी लाई जा सकती है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी केवल पर्यावरणीय परियोजना नहीं, बल्कि औद्योगिक नीति भी है। बैटरी निर्माण, सॉफ्टवेयर, चार्जिंग नेटवर्क, बिजली वितरण, ऑटोमोबाइल विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में लाखों नए रोजगार सृजित हो सकते हैं। यदि भारत इस क्षेत्र में समय रहते निवेश करता है तो वह वैश्विक ईवी आपूर्ति श्रृंखला का महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकता है।

क्या अकाली दल बादल के लिए चुनौती बनेगा वारिस पंजाब दे और अकाली दल

पंजाब दे में शामिल होने और कई अन्य पार्टियों के नेताओं द्वारा वारिस पंजाब दे में शामिल होने के कारण पंथक राजनीति एक बार फिर नए दौर में प्रवेश कर रही है। लंबे समय तक शिरोमणि अकाली दल (बादल) को पंथक राजनीति का मुख्य केंद्र माना जाता रहा लेकिन अब अकाली दल वारिस पंजाब दे और अकाली दल पुनर सुरजीत जैसी ताकतों के सक्रिय होने से राजनीतिक समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह नया राजनीतिक माहौल शिरोमणि अकाली दल (बादल) के लिए चुनौती बन सकता है? कई राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि यह चुनौती मुख्य रूप से अकाली वोट बैंक के बंटवारे के रूप में सामने आ सकती है। शिरोमणि अकाली दल (बादल) का ग्रामीण पंजाब और सिख मतदाताओं में कई दशकों से आधार रहा है लेकिन पिछले कुछ वर्षों में पार्टी को कई राजनीतिक और संगठनात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। इस दौरान अकाली दल वारिस पंजाब दे ने खुद को पंथक मुद्दों की नई आवाज के रूप में पेश करने की कोशिश की है। लोकसभा की 2 सीटें जीतकर इस कोशिश को कामयाबी की ओर बढ़ाया भी है। अकाली दल (अमृतसर) भी लंबे समय से अपने अलग पंथक एजैंडे के साथ सक्रिय है, जबकि अकाली दल पुनर सुरजीत प्रभावशाली शुरूआत करने के बावजूद अकाली दल वारिस पंजाब दे के मुकाबले कुछ कमजोर होता दिखाई दे रहा था। लेकिन अब अकाली दल पुनर सुरजीत के कई नेताओं द्वारा साहनेवाल के गुरुद्वारा रेरू साहिब में पंथक धड़ों को इकट्ठा करने के लिए एक बैठक की गई।

इकबाल सिंह चन्नी

पंजाब के कई राजनेताओं, विशेष रूप से मनप्रीत सिंह अयाली के पुनर सुरजीत अकाली दल छोड़कर अकाली दल वारिस पंजाब दे में शामिल होने और कई अन्य पार्टियों के नेताओं द्वारा वारिस पंजाब दे में शामिल होने के कारण पंथक राजनीति एक बार फिर नए दौर में प्रवेश कर रही है। लंबे समय तक शिरोमणि अकाली दल (बादल) को पंथक राजनीति का मुख्य केंद्र माना जाता रहा लेकिन अब अकाली दल वारिस पंजाब दे और अकाली दल पुनर सुरजीत जैसी ताकतों के सक्रिय होने से राजनीतिक समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह नया राजनीतिक माहौल शिरोमणि अकाली दल (बादल) के लिए चुनौती बन सकता है? कई राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि यह चुनौती मुख्य रूप से अकाली वोट बैंक के बंटवारे के रूप में सामने आ सकती है। शिरोमणि अकाली दल (बादल) का ग्रामीण पंजाब और सिख मतदाताओं में कई दशकों से आधार रहा है लेकिन पिछले कुछ वर्षों में पार्टी को कई राजनीतिक और संगठनात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। इस दौरान अकाली दल वारिस पंजाब दे ने खुद को पंथक मुद्दों की नई आवाज के रूप में पेश करने की कोशिश की है। लोकसभा की 2 सीटें जीतकर इस कोशिश को कामयाबी की ओर बढ़ाया भी है। अकाली दल (अमृतसर) भी लंबे समय से अपने अलग पंथक एजैंडे के साथ सक्रिय है, जबकि अकाली दल पुनर सुरजीत प्रभावशाली शुरूआत करने के बावजूद अकाली दल वारिस पंजाब दे के मुकाबले कुछ कमजोर होता दिखाई दे रहा था। लेकिन अब अकाली दल पुनर सुरजीत के कई नेताओं द्वारा साहनेवाल के गुरुद्वारा रेरू साहिब में पंथक धड़ों को इकट्ठा करने के लिए एक बैठक की गई। इस बैठक में पुनर सुरजीत के कई बड़े नेता शामिल हुए और उनके द्वारा वारिस पंजाब दे, अकाली दल अमृतसर और अन्य पंथक धड़ों के साथ एकता करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी के प्रमुख सदस्य जत्थेदार संता सिंह और इकबाल सिंह झूंदां ने अकाली दल वारिस पंजाब दे के बापू तरसेम सिंह और मनप्रीत सिंह अयाली सहित कई नेताओं के साथ बातचीत की है, हालांकि एक बार पहले भी गठबंधन की कोशिश की गई थी लेकिन वह सफल नहीं हुई थी, पर अब इनके द्वारा एक सांझे एजैंडे पर सहमति बना ली गई है। इस तरह अकाली दल वारिस पंजाब दे और अकाली दल पुनर सुरजीत द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव मिलकर लडने का रास्ता साफ हो रहा है। और इस कमेटी

द्वारा जल्द ही अकाली दल अमृतसर और अन्य पंथक पक्षों के साथ एकता के बारे में बातचीत करने की संभावना है। इस समय अकाली दल बादल के मुकाबले पर अकाली दल वारिस पंजाब दे, अकाली दल पुनर सुरजीत और अकाली दल अमृतसर प्रमुख विपक्षी धड़ों के रूप में गिने जा सकते हैं। अब सोचने वाली बात है कि इस समय इन धड़ों का जन आधार क्या है। अकाली दल वारिस पंजाब दे के प्रभाव की बात करें तो उसने खास तौर पर युवा मतदाताओं और पंथक सोच वाले वर्ग में अपनी पहचान बनाने की कोशिश की है। यदि यह समर्थन और बढ़ता है, तो वह पारंपरिक अकाली वोट बैंक के एक हिस्से को प्रभावित कर सकता है। हालांकि यह प्रभाव पूरे पंजाब में एक जैसा होगा या नहीं, यह अभी स्पष्ट नहीं है। अकाली दल (अमृतसर) लंबे समय से पंथक राजनीति का हिस्सा है। भले ही इसे बड़ी चुनावी सफलता नहीं मिली लेकिन कुछ क्षेत्रों में इसका एक स्थायी समर्थक वर्ग है। यह भी कई हलकों में पंथक वोटों के समीकरण को प्रभावित कर सकता है। अकाली दल पुनर सुरजीत ने राज्य स्तर पर बड़ी ताकत के रूप में शुरूआत की, परंतु नेतृत्व में एकजुटता की कमी के कारण यह धड़ा पहले से कुछ कमजोर हो रहा है, फिर भी जहां इसके बड़े और जन आधार वाले नेता चुनाव लड़ेंगे, वहां यह पार्टी चुनावी मुकाबले को प्रभावित कर सकती है। आखिरी सवाल है कि क्या ये अकाली धड़े अकाली दल (बादल) के लिए बड़ी चुनौती हो सकते हैं? यह कहना कि अकाली दल वारिस पंजाब दे या अन्य धड़ों ने पहले ही शिरोमणि अकाली दल (बादल) का स्थान ले लिया है, तथ्यों के आधार पर ठीक नहीं होगा। लेकिन यह जरूर कहा जा सकता है कि पंथक राजनीति में मुकाबला पहले से काफी बढ़ गया है। शिरोमणि अकाली दल (बादल) के पास अभी भी संगठन, अनुभव और कई क्षेत्रों में पारंपरिक आधार मौजूद है, जबकि नई ताकतें अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। 2027 के चुनावों में यह महत्वपूर्ण होगा कि क्या पंथक वोट एकजुट रहते हैं या कई धड़ों में बंट जाते हैं। इसका प्रभाव न केवल शिरोमणि अकाली दल (बादल) पर, बल्कि पंजाब की समग्र राजनीतिक तस्वीर पर भी पड़ सकता है। परंतु नए बन रहे समीकरणों के कारण यदि बादल विरोधी सभी धड़े इकत्रे हो जाते हैं, तो अकाली दल बादल के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकते हैं।

दिल के रोगों की नाकाबंदी, बनेगा प्रीवेंटिव कार्डियोलॉजी ब्लॉक, जीन स्टडी से पता चलेगा खतरा

कानपुर। कानपुर कार्डियोलॉजी संस्थान में एक नया प्रीवेंटिव कार्डियोलॉजी ब्लॉक बनाया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य दिल की बीमारियों को जड़ से रोकना है। यहाँ अत्याधुनिक जीन स्टडी के साथ-साथ योग, आयुर्वेद और होम्योपैथी जैसी वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों का समावेश होगा, ताकि रोगियों को समग्र (होलिस्टिक) इलाज मिल सके। कानपुर शहर का कार्डियोलॉजी संस्थान तेजी से पांव पसार रहे दिल के रोगों की नाकाबंदी करेगा। इसके लिए संस्थान में प्रीवेंटिव कार्डियोलॉजी ब्लॉक बन रहा है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहां जीन स्टडी से पता चल जाएगा कि संबंधित व्यक्ति या उसके बच्चों को भविष्य में कोई दिल की बीमारी होने का खतरा है या नहीं। ब्लॉक तैयार करने का एकमात्र उद्देश्य बीमारी को पैदा होने या बढ़ने से पहले ही पहचानना और उसे रोकना

है। दो मंजिला इमारत वाले इस विशेष ब्लॉक में कुल छह ओपीडी होंगी। यहां इलाज के पारंपरिक तरीकों से हटकर एक होलिस्टिक अप्रोच (समग्र दृष्टिकोण) अपनाकर रोगियों का उपचार होगा। साथ ही शोध भी किया जाएगा। बदलती जीवनशैली, अत्यधिक तनाव, धूम्रपान, शारीरिक मेहनत न करने से दिल की बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। कॉर्डियोलॉजी के ही आंकड़े बताते हैं कि यहां आने वाले रोगियों की संख्या पिछले दो साल में दोगुनी हो चुकी है। अगर यही रफ्तार रही तो अगले दो साल में ये आंकड़ा चार गुना तक बढ़ सकता है। नए ब्लॉक की सबसे बड़ी खासियत जीन स्टडी इस नए ब्लॉक की बड़ी खासियत है जीन स्टडी। ये इस पूरे प्रोजेक्ट का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहां लोगों के जीन की गहन जांच से पता चल जाएगा कि संबंधित व्यक्ति या उसके बच्चों को भविष्य में कोई दिल की बीमारी होगी या नहीं। अगर खतरा है तो बीमारी कब तक उभर सकती है, जीन स्टडी से वैज्ञानिक और डॉक्टर्स ये भी जान सकेंगे कि भविष्य में होने वाली उस बीमारी पर कौन सी विशेष दवा सबसे ज्यादा कारगर साबित होगी। योग से थमेंगे रोग बीमारी को शरीर में जड़ जमाने से पहले ही रोकने के लिए इस ब्लॉक में एलोपैथी के साथ-साथ प्राचीन और वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। डॉक्टर्स का मानना है कि स्ट्रेस कम करने की कोई रेडीमेड दवा नहीं आती, इसके लिए मेडिटेशन (ध्यान) ही एकमात्र रास्ता है। इस ब्लॉक में रोगियों को योग और ध्यान के जरिए तनावमुक्त रहने का पाठ पढ़ाया जाएगा। साथ ही कार्डियक रिहैबिलिटेशन (पुनर्वास) की सुविधा भी मिलेगी। होम्योपैथी से दुरुस्त होगी शरीर की फिजियोलॉजी होम्योपैथी शरीर की फिजियोलॉजी को दुरुस्त करने का काम करती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी मरीज की नसों में कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हो रहा है तो होम्योपैथी में ऐसी बेहद असरदार दवाएं हैं जो इसे रोक सकती हैं। खास बात यह है कि इसके साथ मरीज की एलोपैथिक दवाएं भी बिना किसी रुकावट के जारी रह सकेंगी। आयुर्वेद के नुस्खे भी अपनाएंगे यहां आयुर्वेद के उन प्रमाणिक तरीकों को भी अपनाया जाएगा जो बीमारियों को बढ़ने से रोकते हैं। इसके तहत न्यूट्रिशन एंड हेल्थ पर विशेष फोकस रहेगा, जहां रोगियों को उनकी बॉडी टाइप के हिसाब से सही डाइट चार्ट प्लान कर दिया जाएगा। ब्लॉक तैयार करने का एकमात्र उद्देश्य बीमारी को पैदा होने या बढ़ने से पहले ही पहचानना और उसे रोकना है। यह ब्लॉक मौजूदा रोगियों का जीवन तो बचाएगा ही, आने वाली पीढ़ी को भी दिल की बीमारियों के चंगुल में फंसने से बचाएगा। यदि बीमारी का रूप बढ़ रहा है तो उसके उपचार और रोकथाम के लिए ये शोध और जागरूकता की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है।

आवास प्लस-2024 सर्वे के बाद सूची से नाम कटा या बदली वरीयता तो 15 तक करें अपील

गाजीपुर। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत आवास प्लस-2024 सर्वे के बाद तैयार की गई स्थायी प्रतीक्षा सूची से यदि किसी पात्र परिवार का नाम हटा दिया गया है या उसकी वरीयता बदल दी गई है, तो उसे अब अपील का मौका मिलेगा। जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने बृहस्पतिवार को इसके लिए जिला स्तरीय अपीलीय समिति गठित कर दी है। संबंधित परिवार 15 जुलाई तक अपनी शिकायत खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) को दे सकते हैं। जिले की सभी ग्राम पंचायतों में निर्धारित रोस्टर के अनुसार ग्रामसभाओं की खुली बैठकों में स्थायी प्रतीक्षा सूची के अनुमोदन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। इस दौरान जिन परिवारों के नाम सूची से हटाए गए या उनके वरीयता क्रम में बदलाव किया गया, उनकी शिकायतों के निस्तारण के लिए यह व्यवस्था की गई है। जिला स्तरीय अपीलीय समिति की अध्यक्षता जिलाधिकारी करेंगे। समिति में मुख्य विकास अधिकारी, परियोजना निदेशक (डीआरडीए) तथा एक नामित सदस्य शामिल होंगे। प्राप्त शिकायतों की पहले संबंधित खंड विकास अधिकारी जांच करेंगे और अपनी रिपोर्ट के साथ समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। समिति के निर्णय के बाद प्रत्येक ग्राम पंचायत की अंतिम स्थायी प्रतीक्षा सूची प्रकाशित की जाएगी।

180 पदों पर होगी आंगनबाड़ी कार्यकताओं की भर्ती, तैयारी शुरू

गाजीपुर। 180 पदों पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की भर्ती निकलने जा रही है। इसकी तैयारियों में बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग जुटा हुआ है। इसको लेकर सभी सीडीपीओ से रिक्त पदों की सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही ब्लॉकवार आरक्षण का खाका तैयार करने की तैयारी शुरू हो गई है। 2024 में 1352 पदों पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भर्ती बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग में हुई थी। इसके बाद यह पहला मौका है, जब विभाग की ओर से एक बार फिर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की भर्ती निकलने जा रही है। भर्ती निकालने को लेकर विभाग की ओर से तैयारी शुरू कर दी गई है। जिले के 17 परियोजना क्षेत्रों से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भर्ती को लेकर पदों की संख्या की सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। इस महीने के अंत तक जिला मुख्यालय पर सभी सीडीपीओ की ओर से अपनी-अपनी सूची उपलब्ध करा दी जाएगी। उधर, किस ब्लॉक में कितने-कितने पद किस जाति के लिए आरक्षित होंगे। इसका खाका तैयार होना शुरू हो गया है। दागदार रही पिछली भर्ती 2024 में बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग की ओर से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के 1352 पदों पर भर्ती निकाली गई थी। इसमें जमकर गड़बड़झाला हुआ था। भर्ती को लेकर 135 शिकायतें आई थीं। 10 लेखपालों को तत्कालीन डीएम आर्यका अखौरी के निर्देश पर निलंबित कर दिया गया था। आरोप था कि कई नियुक्ति कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर कर दी गई थी। साथ ही कई मामले कोर्ट की चौखट पर भी पहुंचे थे।

हादसे में घायल बुजुर्ग की इलाज के दौरान मौत

मथौली। अजीजनगर चौराहे पर 21 जून को हुए हादसे में घायल 60 वर्षीय बुजुर्ग की इलाज के दौरान बृहस्पतिवार को मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कप्तानगंज थाना क्षेत्र के सतभरिया के नान्हूमुरेड़ा निवासी सियाराम राजभर 21 जून को अजीजनगर चौराहे पर बाजार करने जा रहे थे। उसी दौरान बाइक की चपेट में आने वे गंभीर रूप से घायल हो गए। मौजूद लोग उन्हें मथौली सीएचसी भेजवाए, जहां उनकी हालत गंभीर देख डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार कर मेडिकल कॉलेज रविंद्रनगर रेफर कर दिया। वहां उनकी हालत में सुधार नहीं होने पर परिजन उन्हें मेडिकल कॉलेज गोरखपुर ले गए। वहां उनका इलाज चल रहा था। इलाज में सुधार न होने पर परिजन उन्हें को घर लाए। बृहस्पतिवार की सुबह उनकी तबीयत बिगड़ गई। परिजन उन्हें सीएचसी मथौली ले गए, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। सूचना पर आई पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

दरभंगा में मखाना की खेती करना सीखेंगे किसान

पडरौना। जिले के प्रगतिशील किसानों को अब मखाना की उन्नत खेती और आधुनिक कृषि तकनीकों का प्रशिक्षण दिलाने के लिए बिहार के दरभंगा स्थित राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र भेजा जाएगा। साथ ही हरियाणा के करनाल स्थित भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान का भी अध्ययन भ्रमण कराया जाएगा। मुख्य विकास अधिकारी वंदिता श्रीवास्तव ने सभी विकास खंडों से किसानों का चयन कर अध्ययन भ्रमण कराने के निर्देश दिए हैं। कलक्ट्रेट सभागार में सीडीओ वंदिता श्रीवास्तव की अध्यक्षता में कृषि तकनीकी प्रबंधन अभिकरण (आत्मा) के गवर्निंग बोर्ड तथा जिला भूमि एवं जल संरक्षण समिति की विभिन्न योजनाओं की वर्ष 2026-27 की बैठक आयोजित हुई। बैठक में कृषि एवं संबद्ध विभागों की योजनाओं की समीक्षा करते हुए किसानों को अधिकाधिक लाभ पहुंचाने पर जोर दिया गया। बैठक की शुरूआत पिछली बैठक की कार्यवाही की पुष्टि और प्रगति आख्या प्रस्तुत करने से हुई। इसके बाद चूहा नियंत्रण अभियान, फार्मर रजिस्ट्री और विभिन्न कृषि योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, मेरी पुत्री का नाम आधार नं० - 547326079758 में त्रुटिवश अर्शिता अंकित हो गया है, जो गलत है। परन्तु शैक्षिक अभिलेख में प्रतिज्ञा लिखा है, यह कि अर्शिता व प्रतिज्ञा दोनों नाम एक ही व्यक्ति का है। अर्शिता को प्रतिज्ञा किया जाना न्यायहित में अतिआवश्यक है। आज से प्रतिज्ञा के नाम से ही जाना जाये।

झुरूराम यादव पुत्र राम अभिलाष यादव

पता- ग्राम छेछूआ,छेछूआ उपरहार छेछूवान, सन्त रविदास नगर, उत्तर प्रदेश - 221309

सांसद पप्पू यादव ने पर्चे वाले बाबा को बताया नकली, सोशल मीडिया वाले नेताओं पर साधा निशाना

कानपुर। सांसद पप्पू यादव ने 'पर्चे वाले बाबा' पर निशाना साधते हुए उन्हें नकली करार दिया।

साथ ही, उन्होंने बिहार के विकास के लिए नितिन गडकरी से मुलाकात की और सोशल मीडिया आधारित राजनीति करने वाले नेताओं को हवा-हवाई बताते हुए उन पर जमकर तंज कसा। कानपुर पहुंचे सांसद पप्पू यादव ने 'पर्चे वाले बाबा' को घेरते हुए उन्हें नकली बताया। उन्होंने चुनौती भरे लहजे में कहा कि अगर वे सनातन के लिए समर्पित हैं और वास्तव में मरना चाहते हैं, तो मरकर दिखाएं। यदि ऐसा होता है, तो हम गांव-गांव में उनकी मूर्ति बनवाएंगे। बिहार में लगातार गिरते पुलों और एक्सप्रेसवे के लिए फंड की कमी को लेकर उन्होंने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। सांसद ने स्पष्ट किया कि वे कोसी, सीमांचल और पूरे बिहार के अधिकारों के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। उनका जोर बिहार के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर है। सोशल मीडिया वाले नेताओं पर साधा निशाना प्रशांत किशोर और अन्य डिजिटल नेताओं पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर पैसों के दम पर चुनाव नहीं जीता जा सकता। उन्होंने ऐसे नेताओं को हवा-हवाई करार दिया और कहा कि जिन्हें बिहार के गांवों के दर्द का अहसास नहीं है, वे राजनीति में टिक नहीं सकते। कर्ज और भ्रष्टाचार पर चिंता सांसद ने देश की आर्थिक स्थिति पर भी सवाल उठाए। उन्होंने बढ़ते कर्ज और कथित तौर पर देश को आर्थिक गुलामी की ओर ले जाने वाले भ्रष्टाचारियों के खिलाफ मोर्चा खोलने का संकेत दिया। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार और कर्ज का बोझ देश की प्रगति के लिए बड़ा खतरा है।

जामुन तोड़ते वक्त मिली बंदूक, चाचा-भतीजे के साथ हुआ हादसा, अस्पताल में छोड़कर भागे परिजन

कानपुर। घाटमपुर के बलरामपुर में जामुन तोड़ते समय मिली बंदूक से हुए फायर में एक व्यक्ति घायल हो गया था, जिसे परिजनों ने कल्याणपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। 17 दिन बाद जब परिजन बिल जमा करने नहीं आए और मरीज को छोड़कर भाग गए, तब मामला पुलिस के संज्ञान में आया। कानपुर में घाटमपुर थाना क्षेत्र के बलरामपुर में 23 जून को एक दर्दनाक घटना हुई थी। जानकारी के अनुसार, चाचा और उसका 10 वर्षीय भतीजा जंगल में जामुन तोड़ने गए थे, जहां उन्हें झाड़ियों में पड़ी एक बंदूक मिली। घर लाकर जब उन्होंने

बंदूक को खोलने की कोशिश की, तो वह अचानक चल गई और गोली चाचा को जा लगी। हादसे के बाद परिजन घायल को कानपुर के कल्याणपुर स्थित आरोग्य अस्पताल ले गए। पिछले 17 दिनों से उनका उपचार चल रहा था। मामले में मोड़ तब आया, जब दो दिन पूर्व परिजन अस्पताल में अपना बिल बकाया छोड़कर फरार हो गए। शुक्रवार को जब काफी समय बीतने के बाद भी कोई भुगतान के लिए नहीं पहुंचा, तो अस्पताल संचालक ने पुलिस को जानकारी दी। पुलिस की जांच शुरू सूचना मिलते ही कल्याणपुर पुलिस मौके पर पहुंची और तुरंत घाटमपुर पुलिस को सूचित किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसीपी घाटमपुर ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि जंगल में बंदूक कहां से आई और परिजन पुलिस को बिना बताए मरीज को छोड़कर क्यों फरार हो गए।

पति ने बिन बताए की दूसरी शादी, महिला ने युवती को घर पहुंचकर पीटा, पुलिस ने दर्ज किया केस, जांच शुरू

कानपुर। पनकी क्षेत्र में एक युवक द्वारा अपनी पहली शादी की बात छिपाकर दूसरी युवती से कोर्ट मैरिज करने का मामला सामने आया है। सच सामने आने के बाद पहली पत्नी ने दूसरी युवती के घर पहुंचकर मारपीट की, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कानपुर के पनकी थाना क्षेत्र में एक युवक ने शादी की बात छिपा कर दूसरी युवती से कोर्ट मैरिज की। इसका पता जब युवती को चला, तो उसने पति से विवाद किया। इस दौरान पहली पत्नी को पति के प्रेम विवाह की जानकारी हुई, तो वह बारासिरोही निवासी युवती के घर पहुंची और मारपीट की। एसीपी पनकी अमित चौरसिया ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। जांच कर कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस पर युवक को बेरहमी से पीटने का आरोप, शरीर पर चोट के कई निशान, थानाध्यक्ष बोले- आरोप निराधार

कानपुर। बिल्हौर क्षेत्र में एक युवक ने शिवराजपुर थाना पुलिस पर कस्टडी में बेरहमी से मारपीट करने का आरोप लगाते हुए वीडियो वायरल किया है। वहीं पुलिस का कहना है कि युवक पर हाफ मर्डर और युवती का आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने समेत कई गंभीर मुकदमे दर्ज हैं और मारपीट के आरोप पूरी तरह गलत हैं। कानपुर में बिल्हौर थाना क्षेत्र में शिवराजपुर थाना पुलिस पर एक युवक को बेरहमी से पीटने का आरोप लगा है। युवक के खिलाफ थाने में पहले से कई मुकदमे दर्ज है। परिजनों का आरोप है कि दरोगा निजी वाहन से युवक को पकड़कर थाने ले जाने से पहले उसे एक निजी स्थान पर रखकर खूब पीटा। युवक ने घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो में युवक के पूरे शरीर पर चोट के निशान दिख रहे हैं। हालांकि, वायरल वीडियों की पुष्टि संवाद न्यूज एजेंसी नहीं करता हैं। वहीं, थानाध्यक्ष अमित कुमार सिंह का कहना है कि आरोपी के खिलाफ हाफ मर्डर सहित कई घटनाओं में चार मुकदमे दर्ज हैं। अभी हाल मे युवक ने एक युवती के आपत्तिजनक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था, जिसके बाद आरोपी को पूछताछ ले लिए थाने लाया गया था। युवक द्वारा मारपीट के आरोप निराधार गलत है।

राज्यपाल ने छात्रों को दिलाई शपथ, 1071 को उपाधियां और 47 मेधावियों को मिले पदक

कानपुर। एचबीटीयू के दीक्षांत समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की उपस्थिति में 1,071 छात्रों को उपाधियां प्रदान की गईं। साथ ही, शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 47 मेधावियों को पदक देकर सम्मानित किया गया। कानपुर में हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय (एचबीटीयू) का दीक्षांत समारोह शुक्रवार को पूरी भव्यता के साथ आयोजित हुआ। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल उपस्थित रहीं। उन्होंने न केवल मेधावियों को सम्मानित किया, बल्कि भविष्य के लिए छात्र-छात्राओं को शपथ भी दिलाई। स्वर्ण पदक से नवाजे गए प्रज्ञान वर्मा समारोह का मुख्य आकर्षण इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के छात्र प्रज्ञान वर्मा रहे। उन्हें बेहतरीन सीजीपीए अर्जित करने के लिए कुलाधिपति एवं कुलपति स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। उनकी इस उपलब्धि पर पूरा सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। 1071 छात्रों को उपाधियां और 47 मेधावियों को पदक दीक्षांत में 1071 छात्रों को उपाधियां और 47 मेधावियों को पदक दिए गए। कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, वीसी प्रो. समशेर अनिल कुमार राठौर, डॉ. एमके शनमुगा सुंदरम, प्रो. बी परमार, प्रो. वंदना दीक्षित कौशिक आदि मौजूद रहे। सभी ने छात्र-छात्राओं के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दीं।

संक्षिप्त खबरें

चौपाल में लोगों को बताए पेजयल के फायदे

पडरौना। कप्तानगंज क्षेत्र के पडखोरी गांव में बृहस्पतिवर को जल जीवन मिशन के तहत निर्मित ग्रामीण पेयजल योजना परिसर में जल चौपाल एवं जल अर्पण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें लोगों को शुद्ध पेयजल के फायदे बताए गए। गोरखपुर के मुख्य अभियंता (गोरखपुर क्षेत्र) वीपी सिंह ने कहा कि जल जीवन मिशन फेज-2 के तहत पडखोरी गांव में ग्राम पंचायत पेयजल योजना के सोलर पंपिंग प्लांट की स्थापना की गई है। इससे 272 घर को शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो सकेगा। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत लोगों को नियमित रूप से शुद्ध पेयजल मिल रहा है, जिससे उनके स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं जीवनशैली में सकारात्मक परिवर्तन आया है। उन्होंने बताया कि जल जीवन मिशन के फेज-2 एवं फेज-3 के तहत 453 ग्रामीण पेयजल योजनाओं पर कार्य चल रहा है। इन योजनाओं के माध्यम से 667 ग्राम पंचायतों के 904 राजस्व

घर पर गिरा बरगद का पेड़, महिला और दो मासूम घायल

चकिया कोतवाली क्षेत्र के शाहपुर गांव में बुधवार रात एक विशाल बरगद का पेड़ टिनशेड के मकान पर गिर गया। हादसे में मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, जबकि मलबे में दबकर एक महिला और उसके दो मासूम बच्चे घायल हो गए। तीनों का चकिया स्थित संयुक्त चिकित्सालय में इलाज चल रहा है। गांव निवासी गुल्लू राम टिनशेड के मकान में परिवार के साथ रहते हैं। इन दिनों उनकी 25 वर्षीय बेटी वंदना भी अपने दो बच्चों के साथ मायके आई हुई थी। बुधवार रात करीब आठ बजे अचानक मकान के बगल में खड़ा बरगद का पेड़ घर पर गिर पड़ा, जिससे टिनशेड और दीवारें ढह गईं। घर के अंदर मौजूद वंदना, उसकी एक वर्षीय बेटी अनन्या और तीन वर्षीय बेटा बिट्टू मलबे में दब गए। पेड़ गिरने की तेज आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे। उन्होंने कड़ी मशक्कत के बाद पेड़ की टहनियां हटाकर तीनों को बाहर निकाला और तत्काल चकिया स्थित संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती कराया। अस्पताल सूत्रों के अनुसार वंदना के सिर और हाथ में गंभीर चोटें आई हैं, जबकि दोनों बच्चों की हालत खतरे से बाहर है। हादसे में मकान पूरी तरह ध्वस्त हो गया। गृहस्थी का सामान और अनाज भी मलबे में दबकर नष्ट हो गया, जिससे परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हो गया है। ग्राम प्रधान नंदकुमार पाल ने प्रशासन से पीड़ित परिवार को तत्काल आर्थिक सहायता और आवास उपलब्ध कराने की मांग की है। राजस्व टीम ने मौके का निरीक्षण कर क्षति का आकलन शुरू कर दिया है।

कार की टक्कर से बाइक सवार युवक गंभीर घायल

सैयदराजा-जमानिया राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित कंदवा चौराहे के पास बृहस्पतिवार देर शाम तेज रफ्तार कार की टक्कर से बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने एंबुलेंस की मदद से उसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बरहनी पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया। धमीना गांव निवासी 21 वर्षीय विमलेश बाइक से कंदवा स्थित अपने घर लौट रहा था। कंदवा चौराहे के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर पहुंचते ही सैयदराजा की ओर से आ रही एक कार ने उसकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में वह सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि उसकी बाइक भी क्षतिग्रस्त हो गई। दुर्घटना के बाद आसपास के लोगों और दुकानदारों ने तत्काल एंबुलेंस बुलाकर घायल को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बरहनी भिजवाया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसकी गंभीर हालत देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया। हादसे के बाद कार चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया। क्षेत्राधिकारी (सदर) देवेंद्र कुमार ने बताया कि घायल युवक का जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। टक्कर मारने वाली कार की पहचान कर उसकी तलाश की जा रही है।

पशुओं की जांच के लिए तीन लैब, कर्मचारी एक भी नहीं

जिले में पशुओं के इलाज के लिए तीन प्रयोगशालाएं (पैथालॉजी लैब) खोली गई हैं। छह साल में आज तक इन प्रयोगशालाओं में एक भी पशु की जांच नहीं हो सकी। पशुपालकों के लिए लैब सिर्फ एक भवन है। सत्र 2020- 21 में शास्त्री सेतु के पास पशुचिकित्सा विभाग के मंडलीय कार्यालय परिसर में पहला, दूसरा केंद्र सदर अस्पताल में और तीसरा केंद्र हलिया पशु चिकित्सा केंद्र परिसर में खोला गया। उस समय 35 लाख रुपये इन प्रयोगशालाओं के निर्माण पर खर्च किए गए। विभाग की ओर से दावा किया गया कि प्रयोगशालाओं में इंसान की तरह पशुओं के खून, गोबर या मल, लार की जांच की व्यवस्था है लेकिन यहां जांच करने वाला कोई नहीं है। हलिया में लैब टेक्नीशियन की नियुक्ति न होने के कारण रूर्बन मिशन योजना के अंतर्गत निर्मित राजकीय पशु चिकित्सालय के लैब का प्रयोग नहीं हो पा रहा है। संवाद न्यूज एजेंसी मिजार्पुर। पशु चिकित्सालयों में प्रतिदिन 150 पशुओं की ओपीडी होती है। सरकारी तौर पर कोई लैब न होने पर पशुओं की गंभीर स्थिति में पशुपालक बरकछा स्थित बीएचयू के पशु पालन केंद्र जाते हैं या उन्हें वाराणसी जाना पड़ता है।

साक्षात्कार में पहले दिन शामिल हुए 49 अभ्यर्थी

पथरहिया स्थित विकास भवन के सभागार में बृहस्पतिवार को ईसीसीई एजुकेटर के 140 पदों के लिए साक्षात्कार हुआ। पहले दिन 49 अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिए विकास भवन पहुंचे। आवेदन पत्रों के रेंडमाइजेशन के बाद 420 अभ्यर्थियों की सूची बनाई गई थी। इसमें पहले दिन 210 व दूसरे दिन भी 210 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। लेकिन पहले दिन बृहस्पतिवार को मात्र 49 अभ्यर्थी ही साक्षात्कार के लिए पहुंचे। उनके अभिलेखों का परीक्षण कर साक्षात्कार लिया गया। इसके पहले भी ईसीसीई एजुकेटरों के 139 पदों के लिए चयन प्रक्रिया की गई थी, जिसमें से 77 का अंतिम रूप से चयन किया गया था। इनको 13 जुलाई को विद्यालय आवंटन के लिए विकास भवन बुलाया गया है। बीएसए अनिल कुमार वर्मा ने बताया कि यह दूसरे चरण की भर्ती है। पहले चरण में 77 का अंतिम रूप से चयन कर लिया गया है। अब उनको विद्यालय का आवंटन किया जाएगा।

तीन महीने से मौसा किशोरी से करता रहा दुष्कर्म, तबीयत बिगड़ने पर पता चला

क्षेत्र के एक गांव में किशोरी को उल्टी होने पर परिजनों ने डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि वह तीन माह की गर्भवती है। पीड़िता ने बताया कि उसके मौसा ने उसके साथ दुष्कर्म किया जिससे वह गर्भवती हो गई। बुधवार की शाम परिजनों ने थाने में मामले की तहरीर दी। पुलिस किशोरी को मेडिकल के लिए भेजकर मामले की जांच में जुटी है। पिता के अनुसार, 15 वर्षीय किशोरी कक्षा नौ की छात्रा है। गांव में ही मिर्च की फसल पर दवा छिड़काव के बहाने आरोपी उनकी बेटी को घर से ले जाता था। आरोप है कि पिछले तीन माह से वह किशोरी से दुष्कर्म करता रहा। परिवार को इस बात का पता करीब एक सप्ताह पहले चला जब किशोरी की तबीयत खराब हुई। थानाध्यक्ष मड़िहान रविंद्र भूषण मौर्य ने बताया कि पीड़िता के परिजनों की तहरीर मिली है। मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।

पुलिस पर फायरिंग करने वाले तीन बदमाश गिरफ्तार, तमंचे, सूतली बम और बाइक बरामद

असबाबे हिन्दुस्तान,अफजाल कुरैशी
जिला ब्यूरो चीफ /बस्ती

बस्ती- बस्ती पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक संभावित आपराधिक वारदात को समय रहते विफल कर दिया। कोतवाली थाना पुलिस ने टोल प्लाजा क्षेत्र में कथित रूप से किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की तैयारी कर रहे बदमाशों की घेराबंदी की। पुलिस का दावा है कि पीछा किए जाने पर बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद जवाबी घेराबंदी में तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि उनके कई साथी अंधेरे और ट्रैफिक का फायदा उठाकर फरार हो गए, जिनकी तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है।

पुलिस के अनुसार प्रभारी निरीक्षक मोती चंद के नेतृत्व में टीम को सूचना मिली थी कि टोल प्लाजा के पास 8 से 10 मोटरसाइकिलों पर सवार कुछ युवक अवैध तमंचे, देशी सूतली बम, लाठी-डंडे और हॉकी के साथ किसी गंभीर वारदात की योजना बना रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची तो संदिग्ध युवक पुलिस को देखकर बड़ेवन की ओर भागने लगे। पुलिस ने पीछा किया तो आरोप है कि बदमाशों ने पुलिस टीम पर जानलेवा फायरिंग शुरू कर दी।इसके बाद पुलिस ने रणनीतिक तरीके से घेराबंदी करते हुए मुड़घाट पुल के पास एक मोटरसाइकिल पर सवार तीन युवकों को दबोच लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान शिवांश सिंह उर्फ हर्ष निवासी तुर्कहिया, अली खान उर्फ गोलू निवासी तुर्कहिया तथा अहमद खान निवासी जयपुरवा, थाना कोतवाली के रूप में हुई है।तलाशी के दौरान पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से

दो अवैध 315 बोर तमंचे, तीन जिंदा कारतूस, एक देशी सूतली बम, एक मोटरसाइकिल, तीन मोबाइल फोन और 260 रुपये नकद बरामद किए हैं।पूछताछ में आरोपियों ने पुलिस को बताया कि उन्हें अवैध हथियार और सूतली बम उनके साथी अहमद मलिक, जैद और इलहान ने उपलब्ध कराए थे, जबकि गुफरान इद्रीशी ने उन्हें बम बनाने और इस्तेमाल करने का प्रशिक्षण दिया था। पुलिस अब फरार आरोपियों की तलाश में संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही है।

जांच में यह भी सामने आया कि गिरफ्तार आरोपी अली खान के खिलाफ पहले से मारपीट और धमकी के तीन मुकदमे दर्ज हैं, जबकि अहमद खान पर चोरी, लूट, गिरोहबंदी समेत आठ आपराधिक मामले दर्ज हैं। शिवांश सिंह के खिलाफ यह पहला आपराधिक मुकदमा दर्ज हुआ है।इस मामले में कोतवाली पुलिस ने मु0अ0सं0 301/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 109(1), 3(5), विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा-5, आर्म्स एक्ट की धारा 3/25 तथा सीएलए एक्ट की धारा-7 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर तीनों आरोपियों को न्यायालय भेज दिया है।बस्ती पुलिस का कहना है कि अपराध और अपराधियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। पुलिस ने दावा किया कि समय रहते की गई इस कार्रवाई से एक संभावित बड़ी आपराधिक घटना को टाल दिया गया। इस पूरे अभियान में प्रभारी निरीक्षक मोती चंद के नेतृत्व में पांच उपनिरीक्षकों और 12 पुलिसकर्मियों की टीम शामिल रही।

कलयुगी पिता गिरफ्तारः दो सगी नाबालिग बेटियों से दुष्कर्म का आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ा

असबाबे हिन्दुस्तान,अफजाल कुरैशी
जिला ब्यूरो चीफ /बस्ती

बस्ती- बस्ती जिले की कलवारी थाना पुलिस ने रिश्तों को शर्मसार करने वाली एक बेहद गंभीर घटना के आरोपी/ वांछित अभियुक्त (कलयुगी पिता) को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। दो सगी नाबालिग बेटियों के साथ लंबे समय से अनैतिक संबंध बनाने और जान से मारने की धमकी देने वाले इस आरोपी को पुलिस ने मुखबिर की सटीक सूचना पर घेराबंदी कर धर दबोचा। प्राप्त जानकारी के अनुसार, कलवारी थाना क्षेत्र के एक गांव की निवासी 37 वर्षीया पीड़िता ने अपने ही पति रामचरन के खिलाफ एक बेहद संगीन मामला दर्ज कराया था। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि आरोपी पति पिछले काफी समय से अपनी ही 16 और 15 वर्षीय दो सगी बेटियों के साथ डरा-धमकाकर अनैतिक संबंध (दुष्कर्म) बना रहा था। विरोध करने पर वह जान से मारने की धमकी भी देता था।इतना ही नहीं, पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि उसकी ससुराल के लोग अलग-अलग नंबरों से फोन कर मुकदमा न दर्ज कराने के लिए लगातार दबाव बना रहे थे और धमकियां दे रहे थे। इस शिकायत पर कलवारी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बुधवार को आरोपी के खिलाफ धारा 65(1)/351(2) भारतीय न्याय संहिता) एवं 5ठ/6 पाक्सो एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया था।मुकदमा दर्ज होने के बाद से ही आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार फरार चल रहा था। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में एक विशेष टीम का गठन किया गया था। शुक्रवार 10 जुलाई को प्रभारी निरीक्षक कलवारी संतोष कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम को मुखबिर से सटीक सूचना मिली कि आरोपी कहीं भागने की फिराक में है। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने अगौना चौराहे के पास घेराबंदी की और अभियुक्त रामचरन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस द्वारा आवश्यक कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करने के लिए रवाना कर दिया गया है।

हरैया को 504 करोड़ की 77 विकास परियोजनाओं की सौगात, सीएम योगी ने विपक्ष पर साधा निशाना

असबाबे हिन्दुस्तान, अफजाल कुरैशी
जिला ब्यूरो चीफ /बस्ती

बस्ती- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को बस्ती जनपद के विधानसभा क्षेत्र हरैया में आयोजित भव्य कार्यक्रम के दौरान करीब 504 करोड़ रुपये की 77 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया।इस अवसर पर उन्होंने हरैया के विकास कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए मजबूत जनप्रतिनिधित्व जरूरी होता है और हरैया लगातार विकास की नई पहचान बना रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 84 कोसी परिक्रमा मार्ग को श्रद्धालुओं की सुविधा के साथ-साथ अयोध्या रिंग रोड के रूप में विकसित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि भद्रेश्वरनाथ धाम, करण धाम और मखौड़ा धाम समेत प्रदेश के लगभग 1500 मंदिरों का जीर्णोद्धार और सुंदरीकरण कराया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए लगातार कार्य कर रही है।अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले सरकारी धन का दुरुपयोग होता था, जबकि अब संसाधनों का उपयोग धार्मिक, सांस्कृतिक और जनहित से जुड़े विकास कार्यों में किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि पहले गरीबों, दलितों और वंचितों की जमीनों पर अवैध कब्जे होते थे, लेकिन अब प्रदेश में कानून का राज स्थापित हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि बस्ती में कब्रिस्तान के नाम पर हो रहे अवैध कब्जों को हटाने का कार्य भी सरकार ने कराया। विपक्ष पर हमला बोलते हुए मुख्यमंत्री योगी ने समाजवादी पार्टी पर विकास की उपेक्षा, अराजकता और खराब कानून-व्यवस्था का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पहले प्रदेश में सड़क, बिजली और बुनियादी सुविधाओं का अभाव था, जबकि आज हर क्षेत्र में तेजी से विकास हो रहा है। उन्होंने राम मंदिर निर्माण, धार्मिक स्थलों के विकास और बेहतर सुरक्षा व्यवस्था को सरकार की प्रमुख उपलब्धियां बताया।मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के पात्र लोगों तक पहुंच रहा है। गरीबों को मुफ्त राशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, उज्ज्वला गैस कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि, मुफ्त ट्यूबवेल बिजली और मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।उन्होंने जनता से विकास को प्राथमिकता देने वाले जनप्रतिनिधियों को चुनने की अपील करते हुए कहा कि ‘विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित बस्ती, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं।’कार्यक्रम में कृषि मंत्री एवं बस्ती प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही, क्षेत्रीय अध्यक्ष विनोद राय, जिला पंचायत अध्यक्ष संजय चौधरी, भाजपा जिलाध्यक्ष विवेकानंद मिश्रा, हरैया विधायक अजय सिंह सहित कई जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे।

वन महोत्सव के अवसर पर छात्रों ने किया रैली निकल कर दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश

असबाबे हिन्दुस्तान , मुख्य संवाददाता दबीर अब्बास

प्रयागराज। आज वन महोत्सव के अंतर्गत जिला गंगा समिति, प्रयागराज एवं सामाजिक वानिकी वन प्रभाग द्वारा दिल्ली पब्लिक स्कूल में पौधारोपण एवं जनजागरूकता रैली कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम के दौरान छात्र-छात्राओं ने स्लोगन के माध्यम से रैली निकल कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। तथा सभी छात्रों को पौध वितरित किया गया एवं पौधरोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया । इस अवसर पर प्रिंसिपल डॉ. सुजाता सिंह ने विद्यार्थियों को पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित किया। जिला परियोजना अधिकारी एशा सिंह ने विद्यार्थियों को अधिक से अधिक पौधे लगाने तथा लगाए गए पौधों की नियमित देखभाल करने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में शिक्षक शिवाली,श्रीवास्तव,संगीता बालाजी,रीना श्रीवास्तव,संगीता शर्मा,नेहा मखीजा, स्मिता वर्मा एवं अन्य गणमान्य लोगों ने भी पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के जन्मदिन पर स्वच्छता अभियान की शुरूआत

लखनऊ,(संवाददाता)। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के जन्मदिन के अवसर पर शुक्रवार को लखनऊ नगर निगम द्वारा पूरे शहर में मेगा सफाई अभियान चलाया गया। अभियान के तहत नगर निगम के सभी 110 वार्डों में एक साथ विशेष सफाई कार्य कर स्वच्छ, सुंदर और स्वस्थ लखनऊ का संदेश दिया गया। इसका शुभारंभ मेयर सुषमा खर्कवाल ने हजरतगंज स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पार्षदों और नगर आयुक्त गौरव कुमार के साथ पुष्पांजलि अर्पित कर किया। इसके बाद मेयर ने स्वयं सफाई अभियान में सहभागिता करते हुए स्वच्छता का संदेश दिया और नागरिकों से अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखने तथा शहर को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने में सक्रिय भागीदारी की अपील की। इस अवसर पर मेयर सुषमा खर्कवाल ने कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हम सभी के अभिभावक हैं। उनका लखनऊ के प्रति विशेष स्नेह, जनसेवा का भाव और शहर के विकास के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता हम सभी के लिए प्रेरणास्रोत है। उनके जन्मदिन के अवसर पर पूरे लखनऊ में चलाया गया सफाई अभियान सेवा, सम्मान और स्वच्छता के संकल्प की अभिव्यक्ति है। स्वच्छता केवल नगर निगम की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का सामूहिक दायित्व है। जब जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी और आम नागरिक मिलकर स्वच्छता के लिए कार्य करेंगे, तभी लखनऊ को देश के सबसे स्वच्छ और सुंदर शहरों में अग्रणी बनाया जा सकेगा। मेगा सफाई अभियान को प्रभावी, सुव्यवस्थित बनाने के लिए लखनऊ नगर निगम के समस्त 110 वार्डों में नोडल अधिकारियों की तैनाती की गई। नोडल अधिकारियों को अपने-अपने निर्धारित वार्डों में सफाई कार्यों की निगरानी, अभियान के प्रभावी संचालन और व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई।

मुख्यमंत्री ने पूर्व मंत्री मुन्ना सिंह चौहान की प्रतिमा का किया अनावरण

लखनऊ,(संवाददाता)। मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश के पूर्व सिंचाई मंत्री स्व. मुन्ना सिंह चौहान की प्रतिमा का अनावरण किया और श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम ने कहा कि सामान्य परिवार में जन्मे मुन्ना सिंह चौहान संघर्ष के बल पर आगे बढ़े। उन्होंने उत्तर प्रदेश में सिंचाई विभाग के सफल क्रियान्वयन, किसानों के उन्नयन के लिए जीवन समर्पित किया। उन्होंने अमित सिंह चौहान को अपनी विरासत सौंपी। वह भी पिता के सपनों को साकार करने, बीकापुर का विकास करने और डबल इंजन सरकार के विजन को धरातल पर उतारने के लिए मां के सान्निध्य में निरंतर कार्य कर रहे हैं। वह हमारे सामने हर समस्या लाते हैं और हम उसका समाधान कराते हैं।मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम स्थल पर वीर-वीरांगनाओं, महापुरुषों के परिधानों में सजे बच्चों का उत्साहवर्धन किया। बच्चों में भक्ति व देशभक्ति की भावना का संचार किया। उन्होंने बच्चों से हंसी-ठिठोली भी की। मुख्यमंत्री ने हाथ में सेब लेकर भगत सिंह बने बच्चे से पूछा कि यह आलू है क्या, इस पर बच्चों ने तपाक से उत्तर दिया नहीं, सेब है।

प्रयागराज की उभरती गायिका माही निषाद अपने हुनर से बना रही हैं पहचान

असबाबे हिन्दुस्तान, यू पी हेड शकील खान

प्रयागराज के नैनी स्थित सड़वा कॉलोनी, टीएसएल (सारस्वती हाईटेक सिटी) निवासी माही निषाद अपनी मधुर और सुरीली आवाज के दम पर संगीत जगत में लगातार अपनी पहचान बना रही हैं। हाल ही में मुंबई की यात्रा के दौरान उन्होंने कई बड़े कलाकारों से मुलाकात की और अपने गायन प्रतिभा का प्रदर्शन किया।

माही निषाद विशेष रूप से भक्ति गीतों और जागरण कार्यक्रमों में अपनी प्रभावशाली प्रस्तुतियों के लिए जानी जाती हैं। उनकी मधुर गायकी श्रोताओं को भाव-विभोर कर देती है, जिसके कारण उन्हें प्रयागराज की उभरती हुई प्रतिभाओं में गिना जाता है। गायन के साथ-साथ माही निषाद सोशल मीडिया पर भी सक्रिय हैं, जहाँ वे अपने गीतों और संगीत से जुड़े वीडियो साझा करती रहती हैं। उनके बढ़ते हुए प्रशंसक और लगातार मिल रहा स्नेह इस बात का प्रमाण है कि वे अपने हुनर के बल पर संगीत की दुनिया में एक नई पहचान स्थापित करने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रही हैं। प्रयागराज के लोगों को माही निषाद की उपलब्धियों पर गर्व है और सभी उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं।

आवश्यकता है-आवश्यकता है-आवश्यकता है
असबाबे हिन्दुस्तान
हिन्दी समाचार
न्यूज़ चैनल व हिन्दी दैनिक समाचार पत्र में
उत्तर प्रदेश व अन्य प्रदेश में कार्य करने हेतु, संवाददाता,बयूरो चीफ ,फ़ोटो ग्राफर की - शहर व ग्रामीण एरिया में
सम्पर्क करें- समाचार पत्र के मुख्य हेड
दबीर अब्बास से 9919391233-9415842005- प्रयागराज

ताजा खबर...

जन जन कांग्रेस घर-घर कांग्रेस अभियान के तहत मोहम्मद असलम का मालवीय नगर वार्ड में लोगों के घरों में दस्तक

असबाबे हिन्दुस्तान, संवाददाता

प्रयागराज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोहम्मद असलम द्वारा लगभग दो वर्षों से शहर में जन-जन कांग्रेस घर-घर कांग्रेस अभियान चलाया जा रहा है इसी के तहत आज प्रयागराज के मालवीय नगर वार्ड में श्री असलम ने अपने साथियों के साथ लोगों के घरों में दस्तक देकर मुलाकात की तथा बाजारों में भी लोगों

की दुकानों पर पहुंचकर उनसे मुलाकात करके कांग्रेस पार्टी की नीतियों विचारधारा तथा कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए कामों की जानकारी दी श्री असलम में लोगों से कहा कि आज देश में महंगाई बेरोजगारी चरम सीमा पर है आम आदमी को दो समय का भोजन मिलना मुश्किल हो रहा है महिलाओं का उत्पीड़न बढ़ा है देश की संपत्ति को बेचा जा रहा है लोकतंत्र का मजाक बनाया जा रहा है आज जरूरत है देश के संविधान को बचाए रखने की लोकतंत्र को बचाए रखने की कांग्रेस पार्टी ने कई दशकों पर सरकार चलाई जिसमें देश का विकास करने का काम किया आज जरूरत है कि हम सब मिलकर कांग्रेस पार्टी का साथ दें और कांग्रेस को मजबूत करने का काम करें। उक्त अवसर पर सुशील द्विवेदी, दिलावर हुसैन, मोहम्मद अजमल राजू, मोहम्मद नौशाद,असलम वारसी, मोहम्मद साजिद अंसारी, विकास कौशल, शकील अहमद, रईस राईन, अफसर अंसारी, अंकित हेमकर, प्रकाश शर्मा सहित कई लोग शामिल थे।

बैंक से रुपये निकालकर लौट रहे युवक पर हमला, मां-बेटी समेत चार की पिटाई

असबाबे हिन्दुस्तान,अफजाल कुरैशी
जिला ब्यूरो चीफ /बस्ती

बस्ती- कप्तानगंज थाना क्षेत्र के रखिया गांव में बैंक से रुपये निकालकर घर लौट रहे एक युवक पर हमला करने और बीच-बचाव करने पहुंची उसकी मां,बहन व भाई के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़ित परिवार ने थाना कप्तानगंज में तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।तहरीर के अनुसार, ग्राम रखिया निवासी रामरती पत्नी मनीराम ने बताया कि 9 जुलाई 2026 को उनका पुत्र रामकृपाल अपनी मोटरसाइकिल (वढ 51 इह 8045) से भारतीय स्टेट बैंक, ओझागंज रुपये निकालने गया था। बैंक से लौटते समय वनहा मैदान के पास गांव के ही धमेन्द्र पुत्र बाबूराम चौहान तथा उसके दो साथियों ने उसका पीछा कर रोक लिया और गाली-गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी।आरोप है कि रामकृपाल ने फोन कर घटना की जानकारी घरवालों को दी। सूचना मिलते ही उसकी मां रामरती, भाई छोटू और बहन प्रीति मौके पर पहुंचे तो आरोपियों ने उनके साथ भी गाली-गलौज करते हुए लाठी-डंडों से मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। मारपीट में चारों लोगों को चोटें आई हैं।पीड़िता ने थाना कप्तानगंज में तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है।थाना प्रभारी आलोक कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि पीड़िता की तहरीर प्राप्त हुई है। मामले की जांच कराई जा रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी।

राजनाथ सिंह के जन्मदिवस पर सिविल अस्पताल में मरीजों को बांटे गए फल

लखनऊ,(संवाददाता)। केंद्रीय रक्षा मंत्री एवं लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह के 75वें जन्मदिवस पर भारतीय जनता पार्टी लखनऊ महानगर के महामंत्री टिंकू सोनकर के नेतृत्व में आज डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल में भर्ती मरीजों के बीच फल वितरण किया गया। टिंकू सोनकर ने अस्पताल में भर्ती मरीजों का कुशलक्षेम जाना तथा उन्हें फल वितरित कर शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की शुभकामनाएँ दीं। उन्होंने कहा कि राजनाथ सिंह का संपूर्ण सार्वजनिक जीवन राष्ट्रसेवा, संगठन के प्रति समर्पण और जनकल्याण के कार्यों के लिए प्रेरणास्रोत रहा है। उनके जन्मदिवस पर सेवा कार्य करना उनके प्रति सच्ची श्रद्धा एवं सम्मान का प्रतीक है। घ्इस अवसर पर भाजपा महानगर के पूर्व अध्यक्ष एवं एमएलसी मुकेश शर्मा , महानगर उपाध्यक्ष सौरव वाल्मीकि, महानगर मंत्री आनंद पांडे, मंडल अध्यक्ष रिंकू मिश्रा सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

योगी सरकार ने कौशल को बनाया रोजगार का आधार

लखनऊ,(संवाददाता)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हर हाथ को हुनर, हर हुनर को रोजगार के संकल्प को गति देते हुए राजकीय एवं निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण सत्र 2026-27 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 11 जुलाई से शुरू हो रही है। अभ्यर्थी 4 अगस्त की रात्रि 12 बजे तक वेबसाइट ीजजचरूध्ध्ूबअजनच.पद पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल ने बताया कि योगी सरकार ने तकनीकी शिक्षा को उद्योगों की मांग के अनुरूप आधुनिक बनाया है। इस सत्र में अभ्यर्थी राजकीय एवं निजी आईटीआई में संचालित सभी व्यवसायों के साथ-साथ टाटा टेक्नोलॉजी के सहयोग से 211 राजकीय संस्थानों में संचालित हो रहे 10 नए दीर्घकालीन व्यवसायों में भी प्रवेश ले सकेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी की आईटीआई अब केवल प्रशिक्षण केंद्र नहीं, बल्कि रोजगार की गारंटी बन रही हैं।

प्रबन्ध सम्पादक
दबीर अब्बास
सम्पर्क–9919391233,
9415842005

हिन्दी दैनिक असबाबे हिन्दुस्तान

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक शबीना खातून द्वारा रमा प्रिन्टिग प्रेस, 53/25/1,ए–बेली रोड, नया कटरा, **इलाहाबाद** से मुद्रित कराकर, 46ए/9, करबला **इलाहाबाद** से प्रकाशित।

सम्पादक
शबीना खातून
फोन– 7499536747

Email:
asbabehindustannews@gmail.com

R.N.I.NO.:UPHIN/2013/49660

इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं सम्पादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अर्न्तगत उत्तरदायी तथा उत्पन्न समस्त विवाद इलाहाबाद न्यायालय के अधीन ही होंगे।